National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multinationaljournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 22-02-2026, Accepted: 25-03-2026, Published: 09-04-2026
Volume 11, Issue 2, 2026, Page No. 30-33

भारतीय संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण कानून की भूमिका

भागीरथ पटेल
शोधार्थी, विधि विभाग, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
कोई भी संविधान पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों से संबंधित नहीं है, क्योंकि किसी भी संविधान में केवल शक्ति संरचना, आवंटन और प्रयोग के तरीके से संबंधित कानूनों के नियम होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान पहले से ही एक भारी दस्तावेज है और संक्षिप्तता एक आदर्श संविधान का चरित्र है। इसलिए संवैधानिक कानून के सिद्धांतों के साथ–साथ संविधान की लंबाई के दृष्टिकोण से, स्वस्थ पर्यावरण की रक्षा करने वाला ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था। इसलिए, बाद के संशोधन तक भारत का संविधान पाठ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के बिना था। हालाँकि, इस तरह के प्रावधान के बीज संविधान के अनुच्छेद 47 में देखे जा सकते हैं जो राज्य को जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बदनामी में सुधार करने का आदेश देता है। इस संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए।
यह शोधपत्र भारतीय पर्यावरण संरक्षण कानून और नीति से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण, स्रोत और प्रभाव, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कानून, पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका और बहुत कुछ शामिल है।

मूल शब्दः प्रदूषण, पर्यावरण, पर्यावरण विधान, पर्यावरण कानून, शक्ति संरचना, पर्यावरण क्षरण, शहरीकरण, संवैधानिक प्रावधान

भारत में पर्यावरण संरक्षण की चिंता को न केवल देश के मौलिक कानून के दर्जे तक उठाया गया है, बल्कि यह मानवाधिकारों के दृष्टिकोण के साथ भी मिला हुआ है और अब यह अच्छी तरह से समझा और आवश्यक है कि मानव गरिमा के साथ स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों में निहित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "सतत विकास" की आवश्यक विशेषता जैसे "एहतियाती सिद्धांत" और "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" देश के पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो इसमें पर्यावरण पर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था और यहां तक कि "पर्यावरण" शब्द भी संविधान में नहीं थाय ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो काफी हद तक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर थे जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन का संगठन और प्राकृतिक स्मारकों का संरक्षण आदि।

पर्यावरण की सुरक्षा में संवैधानिक प्रावधान

भारत में पर्यावरण संरक्षण की चिंता को न केवल देश के मौलिक कानून के दर्जे तक उठाया गया है, बल्कि यह मानवाधिकारों के दृष्टिकोण के साथ भी मिला हुआ है और अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि पूर्ण मानव गरिमा के साथ प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण में रहना प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों में निहित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "सतत विकास" की आवश्यक विशेषता जैसे "एहतियाती सिद्धांत" और "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" देश के पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं। जब हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो इसमें पर्यावरण पर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था और यहां तक कि "पर्यावरण" शब्द को भी संविधान में जगह नहीं मिली थीय ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनका पर्यावरण पर काफी हद तक सीधा असर पड़ा जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन का संगठन और प्राकृतिक स्मारकों को तोड़–फोड़, विरूपण आदि से संरक्षण।

संविधान और पर्यावरण संबंधी कानून की प्रस्तावना

हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि हमारा देश समाज के "समाजवादी" स्वरूप पर आधारित है, जहां राज्य व्यक्तिगत समस्याओं की तुलना में सामाजिक समस्याओं के बारे में अधिक चिंतित है। पर्यावरण प्रदूषण, जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक के रूप में उभरा है, को बड़े पैमाने पर समाज में एक वास्तविक समस्या के रूप में माना जा रहा है और इसलिए राज्य समाजवाद के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाध्य है, अर्थात सभी को बुनियादी और सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना, जिसे प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण से प्राप्त किया जा सकता है।
प्रस्तावना में आगे घोषणा की गई है कि भारत के लोग जिन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का इरादा रखते हैं, उनमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल हैं। न्याय में पर्यावरण न्याय भी शामिल है। यद्यपि विशेष शब्द "पर्यावरण" का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, हम स्वयं पर्यावरण न्याय को शामिल करने के लिए इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पर्यावरण एक विषय वस्तु के रूप में हमारे दैनिक जीवन में इस तरह से प्रवेश कर गया है कि हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 48, और 51, (1) (जी)

भारत सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए इन अनुच्छेदों में संशोधन करते हुए संविधान के 42वें संशोधन को लागू किया। पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 48, और अनुच्छेद 51, (1) (जी) में संशोधन लाया गया।
अनुच्छेद 48ए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अलावा जुड़ा हुआ था। इसमें कहा गया है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" इस अनुच्छेद में आगे बताया गया है कि पहले से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा

करना और संरक्षण और संरक्षण के विभिन्न तरीकों से पर्यावरण में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि देश के आसपास के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।

अनुच्छेद 51, (1) (जी)

यह मौलिक कर्तव्यों के अतिरिक्त भारत के नागरिकों को दी गई एक जिम्मेदारी है। इसमें कहा गया है, "वन, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना।" अनुच्छेद 48, के समान है, लेकिन अंतर केवल यह है कि भारत के नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य के रूप में कर्तव्य दिया गया है कि एक बार प्रत्येक नागरिक को परिवेश की रक्षा करने का संवैधानिक कर्तव्य देना है (अनुच्छेद. 51,) राष्ट्र को राज्य एजेंसियों के खिलाफ उस कर्तव्य को लागू करने में अदालत की सहायता को सूचीबद्ध करने का संयुक्त रूप से अधिकार होना चाहिए। अदालत ने प्रशासन को पूरे शहर को साफ करने के लिए छह महीने का समय दिया, और धन और कर्मचारियों की कमी की याचिका को खारिज कर दिया।

अनुच्छेद 246:

संविधान का अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच विधान के विषय क्षेत्रों को विभाजित करता है। संघ सूची (सूची I) में रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, अप्रत्यक्ष परिवहन, नौवहन, हवाई तस्करी, तेल क्षेत्र, खदानें और अंतर–राज्यीय नदियाँ शामिल हैं। राज्य सूची (सूची II) में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जल आपूर्ति, सिंचाई और खाली करना, मत्स्य पालन शामिल हैं। समवर्ती सूची (सूची III) (जिसके तहत प्रत्येक राज्य और संघ भी कानून बनाएगा) में वन, वन्यजीवों, खानों और खनिजों का संरक्षण और विकास जो संघ सूची में शामिल नहीं हैं, जनसंख्या नियंत्रण और कारखाने शामिल हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, विधायी प्राधिकरण का आवंटन एक महत्वपूर्ण है–स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान जैसे कुछ पर्यावरणीय दोष, स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छा उपायय अन्य, जैसे प्रदूषण और वन्यजीव संरक्षण, उच्च विनियमित समान राष्ट्रीय कानूनों को मापते हैं।

अनुच्छेद 253:

संविधान का अनुच्छेद. 253 संसद को भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, इसके अलावा किसी वैश्विक सम्मेलन, संघ या वैकल्पिक निकाय में बनाए गए किसी भी आह्वान के रूप में। अनुच्छेद. 253 में कहा गया है, "फिर भी इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंध उपबंधों के भीतर, संसद को दूसरे देश या देशों के साथ किसी संधि, करार या अभिसमय को अधिनियमित करने के लिए भारत के राज्यक्षेत्र के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। 1980 में तिवारी समिति ने पर्यावरण विषयों पर अधिनियमित करने के लिए केंद्र द्वारा संशोधित समवर्ती सूची में "पर्यावरण संरक्षण" पर एक नई प्रविष्टि लाने का विचार रखा, क्योंकि 7वीं में कोई प्रत्यक्ष प्रविष्टि संसद को व्यापक पर्यावरण कानून बनाने में सक्षम नहीं बनाती थी।

अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी)

अनुच्छेद 14 में कहा गया है, "यह राज्य का कर्तव्य है कि वह भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के साथ कानून के समक्ष समान या समान संरक्षण का व्यवहार करे। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले सरकारी निर्णयों से भी समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। समानता के अधिकार से इनकार को साबित करने के लिए कई पर्यावरण समूह अक्सर विकास नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण के लिए मनमाने ढंग से नगरपालिका की अनुमति को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 14 की मांग करते हैं।

अनुच्छेद 21:

"प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा जब तक कि कानून द्वारा प्रतिबंधित या कानून का विरोध न हो।"

मेनका गांधी बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कला के तहत "जीवन के अधिकार" के महत्व को स्पष्ट करते हुए। 21 ने अभिनिर्धारित किया कि जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बुनियादी मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार तक फैला हुआ है। इसी प्रकार गंगा प्रदूषण मामले में अनुच्छेद. 21 की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने प्रदूषणकारी चमड़ा कारखानों को बंद करने को न्यायोचित ठहराते हुए कहाः "हम इस बात से अवगत हैं कि चमड़ा कारखानों को बंद करने से बेरोजगारी, राजस्व की हानि हो सकती है, लेकिन जीवन। लोगों के लिए स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी का अधिक महत्व है।

संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव

भारत के संविधान ने भारत में पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए संविधान के 42वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 48, और 51, (1) (जी) को पेश किया है। इतने सारे संशोधनों और कार्यान्वयन के बाद भी हम देख सकते हैं कि राज्य के साथ–साथ लोग भी पर्यावरण के संरक्षण पर कम ध्यान देते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में नियमों का कोई अनिवार्य कार्यान्वयन नहीं है। हम अभी भी एक विकासशील देश हैं और देश के कई हिस्सों में गरीबी व्याप्त है। लोग पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के बारे में पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं। यदि कानून पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों पर सख्त सजा लागू करता है तो पर्यावरण का पालन करने और संरक्षित करने का बेहतर कारण हो सकता है। हम आगे विभिन्न मामलों के अध्ययन और अनुसरण किए गए तरीकों या नीतियों द्वारा पर्यावरण के संरक्षण पर संवैधानिक प्रावधानों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

भोपाल गैस त्रासदी मामला

भोपाल त्रासदी ने अधीनस्थों के कार्यों के लिए मूल फर्मों के दायित्व, असुरक्षित गतिविधियों में लिप्त अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की जिम्मेदारियों, असुरक्षित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और दायित्व के लागू सिद्धांतों पर कई कानूनी प्रश्नों को आमंत्रित किया है। असुरक्षित प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कंपनी देयता के विकसित सिद्धांतों के दायरे में न्यायिक नवाचार के लिए भोपाल एक पवित्र मुद्दा था।

3 दिसंबर, 1984 को, अत्यधिक हानिकारक एल्किल रेडिकल आइसोसाइनाइड्स (एम. आई. सी.) जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में निर्मित और रखे गए थे, वातावरण में मुक्त हो गए और 3500 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 100000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

भोपाल गैस त्रासदी (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985 को यह सुनिश्चित करने के लिए संसद में पारित किया गया था कि भोपाल आपदा से उत्पन्न होने वाले दावों को प्रभावी ढंग से, समान रूप से और दावेदारों के सरलतम लाभ के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

ताजमहल मामले में (एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार, ए. आई. आर. 1997/ एस. सी. 734) सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि ताज ट्रैपेजियम (टी. टी. जेड.) में कोयला और कोक आधारित उद्योग जो ताज को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें

या तो गैस में परिवर्तित किया जाना चाहिए या टी. टी. जेड. के बाहर पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने वन विभाग द्वारा ताज के आसपास लगाए गए पौधों की रक्षा करने का निर्देश दिया:

यह देखना संभागीय वन अधिकारी का कर्तव्य है कि पौधों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। केंद्र सरकार का कर्तव्य धन उपलब्ध कराना है। फंडिंग भी बाद में U-P- के साथ निपटाई जाती है। हालाँकि, सरकार को किसी भी परिस्थिति में धन की आवश्यकता के लिए अधिकारी को उन पौधों की कल्पना करने का निर्देश दिया जाता है जो पानी नहीं देते हैं।

न्यायालय का यह नियंत्रण है कि शहर में स्थापित और चालू 292 उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर औद्योगिक ईंधन के रूप में गैस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या कोकध्कोयले के साथ काम करना बंद कर देना चाहिए और पुनर्स्थापित होना चाहिए। गैस के लिए आवेदन नहीं करने वाले उद्योग या 30.04. 1997 से कोयले के साथ काम करने से रोकने के लिए पुनर्स्थापित उद्योग. शहरी कार्यक्रम के प्रावधान और साथ ही प्रलोभन आमतौर पर नई औद्योगिक इकाइयों तक बढ़ाया जाता है।

भारतीय कानूनी ढांचे में पर्यावरण कानून के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का एकीकरण पर्यावरण कानून के दायरे में जनहित न्यायिक कार्यवाही के उद्भव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। वास्तव में, भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों का अनुप्रयोग और पुनः व्याख्या पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति खतरनाक औद्योगिक उद्यमों को जिम्मेदार बनाने के साथ एक बड़ी चिंता को दर्शाती है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को तैयार करने के लिए अंग्रेजी कानून में रायलैंड बनाम फ्लेचर्स मामले से सख्त दायित्व के सिद्धांत का विस्तार किया है, जिसके तहत एक खतरनाक गतिविधि करने वाला उद्यम ऐसी गतिविधि से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए "पूरी तरह से उत्तरदायी" है। अंग्रेजी सामान्य कानून में सख्त दायित्व के सिद्धांत में कहा गया है कि "एक व्यक्ति तब सख्त उत्तरदायी होगा जब वह अपनी भूमि पर कुछ ऐसा लाएगा या जमा करेगा जिससे नुकसान होने की संभावना है, और इसके भागने के प्राकृतिक परिणाम के रूप में नुकसान होता है।"

एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (वाहन प्रदूषण मामला)

संविधान के अनुच्छेद 48 के संदर्भ में पुरानी दिल्ली शहर में यातायात प्रदूषण से संबंधित एक मामला एम. सी. मेहता बनाम एशियाई राष्ट्र संघ (वाहन प्रदूषण मामला) में विचार के लिए आया था। यह सरकार का कर्तव्य होने का आदेश था। यह पता लगाने के लिए कि परिवहन प्रदूषण के कारण हवा दूषित नहीं हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर इस बात की पुष्टि करता है कि स्वस्थ पर्यावरण एक बुनियादी अधिकार है। व्यक्त किया कि हवा को धोने का अधिकार अतिरिक्त रूप से अनुच्छेद इक्कीस से उत्पन्न हुआ है जिसमें जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह मामला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि पुरानी दिल्ली में सीसा रहित हाइड्रोकार्बन प्रस्ताव पेश किया गया था। अदालतों के निर्देश के अनुसार पिछले औद्योगिक वाहनों को पांच साल पहले पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। पुरानी दिल्ली अपनी उपहार वायुमंडलीय स्थिति का श्रेय स्वच्छ हवा को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास को देती है।

पर्यावरण पर मानव प्रभाव

मानव सामाजिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच बातचीत के आधार पर, पृथ्वी पर सभी आवासों को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: बसे हुए, निर्जन या गतिहीन। पर्यावरण में पाँच बुनियादी मानव आवश्यकताएँ ऑक्सीजन, पानी, भोजन, आश्रय और गर्मी हैं। मनुष्य पर्यावरण को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। अत्यधिक संसाधन की खपत पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को कम करती है, जिसे पारिस्थितिक पदचिह्न द्वारा मापा जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और बाजारों के विकास ने कृषि, वानिकी और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। वनों की कटाई और वाहनों के निकास से वायु प्रदूषण होता है। जल निकायों में सीवेज, घरेलू, कृषि और औद्योगिक कचरे का निर्वहन विषाक्त रसायनों से जल निकायों को दूषित कर सकता है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाइड्रोथर्मल संदूषण का एक अन्य स्रोत बिजली संयंत्रों और औद्योगिक संयंत्रों में ठंडे पानी का उपयोग है। आने वाली बिजली का अत्यधिक उपयोग अक्सर त्वचा के जलने, हृदय रोग और कैंसर का कारण बनता है।

पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2024

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में एक अतिरिक्त संशोधन के रूप में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी, 2024 को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2024 जारी किए गए थे। आगामी संशोधन को स्पष्ट किया गया है: अनुसूची–1 में "फिलामेंट यार्न इकाइयों" शब्दों के बाद "निरंतर काता यार्न प्रौद्योगिकी से उत्पादन को छोड़कर" शब्द जोड़े गए हैं, जो मानव निर्मित फाइबर से संबंधित क्रम संख्या 2 में "मानव निर्मित फाइबर उद्योग के लिए पर्यावरण मानक" शीर्षक के तहत "नोट" खंड में उपशीर्षक "प्रवाह मानक" के तहत "पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक" बताता है।

राज्यसभा ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 पारित किया

एक विधेयक जिसका उद्देश्य छोटे जल प्रदूषण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों के लिए पद की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देना और विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों को कानूनी बाधाओं से छूट देना है, को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 पेश करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास एक साथ होना चाहिए।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, संशोधन आपराधिक कानूनों को तर्कसंगत बनाने और यह गारंटी देने का प्रयास करता है कि लोग, व्यवसाय और कंपनियां मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघन के लिए जेल के डर के बिना काम करें।

विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास धारा 25 को माफ करने का अधिकार होगा, जो एक विशिष्ट वर्ग के औद्योगिक संयंत्रों के लिए नए आउटलेट और डिस्चार्ज पर प्रतिबंध लगाता है।

प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों के लिए नामांकन प्रक्रिया संघीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी। इसके अतिरिक्त, यह केंद्र सरकार को किसी उद्योग की स्थापना, किसी प्रक्रिया के संचालन, उपचार और निपटान प्रणाली, या नव निर्मित या संशोधित आउटलेट के उपयोग के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति देने, इनकार करने या रद्द करने के संबंध में दिशानिर्देश स्थापित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं और पर्यावरण को अधिकार क्षेत्र से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। लेकिन कानूनों, विनियमों और अधिकारों के बावजूद, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण अभी भी एक बड़ी समस्या है। बड़ी सामाजिक समस्या जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे पास कई संघीय और राज्य कानून हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उन्हें लागू करना मुश्किल है। महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, एक पर्यावरण संरक्षण कानून होना चाहिए जिसे लागू किया जाना चाहिए। अपराध आयोग के पास दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्ति है और उसे निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। इन क्रमांकित कानूनों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू करने के लिए, प्रत्येक इलाके में क्रमांकित पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। न्यायाधीश कार्य में तेजी लाने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्य कर सकते हैं और इसकी देखरेख कर सकते हैं, लेकिन इसे जनता द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। अंत में, न केवल सरकारी जिम्मेदारियों, बल्कि नागरिकों को भी पर्यावरण की रक्षा, नियंत्रण और संरक्षण के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। इस कारण से, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक कानूनी प्रणाली और अन्य पर्यावरण कानूनों की दक्षता प्रभावित नहीं होगी। भारतीय कानून में गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण कानून हैं। इसलिए, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को अप्रभावित रखने के लिए संवैधानिक जनादेश और अन्य पर्यावरण कानूनों के प्रभावी और कुशल प्रवर्तन की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. गुरदीप सिंह, भारत में पर्यावरण कानून, मैकमिलन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2009
2. जी इंदेरा प्रिया दर्शिनी और ज्ञ.न्उं देवी, पर्यावरण कानून और सतत विकास, रीगल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010।
3. डॉ. पी. के. राणा, पर्यावरण संरक्षण पर संवैधानिक और न्यायपालिका परिप्रेक्ष्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ
4. सी. पी. आर. पर्यावरण शिक्षा केंद्र, भारत के पर्यावरण कानून और परिचय।
5. पी. दीपा, पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण, भारत में लोकतंत्र का भविष्य, आईएसबीएन 978–93–5391–555–1, यूनिटी कॉलेज प्रकाशन, लखनऊ, 2020।
6. गिल, जी.एन. (2012), भारत में मानवाधिकार और पर्यावरण, जनहित याचिका के माध्यम से पहुंच। पर्यावरण कानून समीक्षा, 14(3), 200।
7. स्मिता सतपति, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान, जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी लीगल रिसर्च, आईएसएसएनः 2582–9947, खंड 2, अंक 1, 2022।
8. मजूमदार, जे. (2017, 14 जनवरी), "विकास विरोधी" अभ्यावेदन के मनोरंजन के खिलाफ पर्यावरण पैनल। इंडियन एक्सप्रेस
9. कैलाश ठाकुर, भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून और नीति, डीप एंड डीप पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2013।
10. घोष, एस. (2019), भारतीय पर्यावरण कानून प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत। ओरिएंट ब्लैकस्वान।
11. एस. सी. शास्त्री, पर्यावरण कानून, फिथ संस्करण, ईस्टर्न बुक कंपनी।
12. एस. शांतकुमार का, पर्यावरण कानून का परिचय, दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रण 2010, लेक्सिस नेक्सिस, नागपुर, 2010।